www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 330 | जौनपुर, मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

6 सांसदों के विलय की वैधानिकता पर छिड़ी बहस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। शिवसेना (उबाठा) ने अपने छह सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मंजूरी दिए जाने को चुनौती देते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। शिवसेना (उबाठा) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। कामत ने पीठ से आग्रह किया कि याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम देखेंगे।'' कामत ने पीठ को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना (उबाठा) के छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा, ''अध्यक्ष ने छह सांसदों के विलय को मान्यता दे दी है।'' कामत ने दलील दी कि यह राष्ट्रीय स्तर पर एक नया चलन बन गया है, जिसमें सांसद उन दलों में शामिल हो रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले 18 जुलाई को शिवसेना (उबाठा) के छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने को मंजूरी दी थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन छह सांसदों को मिला कर लोकसभा में शिवसेना की सदस्य संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने स्वयंभू बाबा आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। आसाराम ने चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की है, जिस पर विचार करने के लिए अदालत ने यह आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि गठित मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर अदालत को सौंपे। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27 मई को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 80 वर्ष से अधिक आयु के आसाराम की दोषसिद्धि और उसे निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि महज तीन महीने पहले ही आसाराम ने काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि उसे इस आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी कि वह अचेत अवस्था में है, लेकिन अब वह घूम–फिर रहा है। इस दलील पर पीठ ने कहा कि वे अभी नियमित जमानत नहीं दे रहे हैं।

आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, दोषियों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षामें धांधली और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्र की मंगल मिशन बैठक में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए बैठक में नेताओं को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसी भी गड़बड़ी के कारण छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, हम छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज की इजाजत नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। नीट में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों से भी अपील की कि जहाँ कहीं भी ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आएं, वहां बिना किसी ढिलाई के त्वरित व सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि योग्य उम्मीदवारों का समय और भविष्य प्रभावित न हो, इसके लिए पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम भी समय पर घोषित किए गए।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगे आकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी साझा किया कि वह पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात करने भी जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने विपक्ष के कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि छात्रों से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर सदन के भीतर विस्तार से चर्चा कराई जाए। अपनी इस मुलाकात के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा कराने का अनुरोध किया, जिस पर अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस संबंध में उन्हें पहले सरकार से बात करनी होगी। कांग्रेस नेता ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये युवा बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र जो कह रहे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और विपक्ष भी पूरी तरह उनके साथ है। राहुल गांधी ने मांग की कि प्रधानमंत्री को छात्रों पर पुलिस का बलप्रयोग बंद करवाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए।

50 हजार छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, पेट्रोल और हेलमेट भी देगी सरकार

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आधारभूत ढांचे के विस्तार, महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को स्कूटी देगी। इसका फायदा उन छात्राओं को होगा, जिनके परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए तक होगी। स्कूटी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5: छात्राओं को ही मिलेगी। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना, महिला छात्रावास शामिल है। इसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है।

करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलेगा।साथ ही पेट्रोल और हेलमेट भी सरकार देगी। योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रकार के कॉलेजों की स्नातक अंतिम वर्ष की टॉप–5 छात्राएं पात्र होंगी। लाभ के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होना जरूरी है। वहीं दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन वर्गों के लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही पात्रता होगी।

अचानक सीजेपी विरोध प्रदर्शन में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंच गए जेपी नड्डा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राजधानी के राम मनोहर लोहिया (ट्डस्) अस्पताल का दौरा किया। वे सोमवार को ब्श्रच के विरोध मार्च के बाद पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए लोगों से मिलने गए थे। नड्डा अस्पताल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल होने के बाद इलाज के लिए भर्ती लोगों से बातचीत की। अपने दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक भी की ताकि घायलों की हालत और उन्हें दी जा रही मेडिकल देखभाल का जायजा ले सकें। इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने और घायलों से मिलने के बाद नड्डा अस्पताल से चले गए। नड्डा के अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्डस् अस्पताल में घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। सोमवार को संसद की ओर भाजपा का विरोध मार्च हिंसक हो गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि झड़पों में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। साथ ही, लगभग 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकीं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और सरकारी गाड़ियों में तोड़–फोड़ की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट में हुई कथित तोड़–फोड़ और पत्थरबाजी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला और कई मांगें रखीं, जिनमें प्रधान का इस्तीफा, जान गंवाने वाले नीट उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और सफदरजंग अस्पताल में इलाज करा रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई शामिल है।

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को फडणवीस का समर्थन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को जंतर– मंतर पर सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव की। उन्होंने कहा कि हालांकि सभी को शांतिपूर्ण विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, बिना अनुमति के प्रदर्शन करना और हिंसा का सहारा लेना स्वीकार्य नहीं है। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करना या हिंसा का सहारा लेना किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए फड़नवीस ने कहा, श्लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। हालांकि, विरोध करते समय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और इसके द्वारा निर्धारित जिम्मेदारियों दोनों को ध्यान में

रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उचित अनुमति के साथ शांतिपूर्ण विरोध करता है, तो ऐसी अनुमति दी जाएगी,। हर किसी को ऐसे विरोध करने का अधिकार है। दूसरी ओर, जानबूझकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, बिना अनुमति के विरोध करना या हिंसा का सहारा लेना किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब कोई आंदोलन चेहराविहीन या नेतृत्वविहीन हो जाता है, तो कुछ तत्व उसमें घुसपैठ करने लगते हैं और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उस मंच का दुरुपयोग करते हैं। पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन सोमवार की स्थिति में पुलिस को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध–प्रदर्शन को सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया। उन्होंने इसे नाटक बताया। इसके साथ ही दावा किया कि युवाओं में जो गुस्सा दिख रहा है, वह बनाया–बनाया (मनगढ़ंत) है।

किसानों की तरह छात्रों के प्रति भी मोदी सरकार असंवेदनशील और उदासीन है – जयराम रमेश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की तरह लाखों छात्रों और युवाओं की गंभीर चिंताओं के प्रति भी असंवेदनशील और उदासीन है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में यह दावा भी किया कि ठीक एक साल पहले तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पांच साल के कार्यकाल के तीन वर्ष बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े धूमधाम से धनखड़ को पद पर लाए थे लेकिन किसानों की दुर्दशा और पीड़ा तथा मोदी सरकार की उनके प्रति चौंकाने वाली असंवेदनशीलता पर बार–बार अपनी व्यथा व्यक्त करने के कारण धनखड़ को अचानक पद छोड़ना पड़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसी तरह की असंवेदनशीलता और उदासीनता अब लाखों छात्रों और युवाओं की गंभीर चिंताओं के मामले में भी पूरी तरह दिखाई दे रही है। रमेश ने कहा कि धनखड़ को राज्यसभा के सदस्यों की ओर से औपचारिक विदाई देने का शिष्टाचार भी नहीं दिखाया गया। पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान 21 जुलाई को तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया था।

भाजपा विदेशी लुटेरों की तरह काम कर रही, छात्रों का भविष्य बर्बाद किया – अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा विदेशी लुटेरों की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा, विश्वविद्यालयों को नष्ट किया और आंदोलनों को दबाया, उसी प्रकार भाजपा सरकार भी लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अहंकार में काम कर रही है और जनता, छात्रों तथा युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है।सोमवार को संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ और पेपर लीक के कारण कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उन छात्रों के प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर जंतर–मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय उनके साथ सख्ती बरती और लाठीचार्ज कराया।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उनका दावा था कि उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए, लेकिन अब तक किसी भी बड़े दोषी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक के मामलों में सत्ता से जुड़े लोगों की भूमिका होने के कारण कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामलों को लेकर एक ऑडिट रिपोर्ट भी प्रकाशित की है।उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहती।

डीआरएम रेलवे सुनील वर्मा ने किया अयोध्या कैंट व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार श्रीवास्तव

अयोध्या। मंगलवार को डीआरएम रेलवे लखनऊ मंडल सुनील वर्मा ने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।इससे पहले उन्होंने रुदौली विधायक राम चन्दर यादव के साथ रुदौली रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया।उन्होंने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित वाशिंग लाइन,सभी प्लेटफॉर्मों, आरक्षण केंद्र, वेटिंग हॉल सहित अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद लखनऊ रेलवे मंडल से आए अन्य अधिकारियों तथा कैंट रेलवे स्टेशन के अधिकारियो से वाहन पार्किंग को लेकर बातचीत किया।उन्होंने खुद माना कि यहां पर सबसे बड़ी गंभीर समस्या पार्किंग की है।क्योंकि पार्किंग ना होने के चलते यहाँ पर ट्रेनों के आने और जाने वाले रेल यात्रियों के साथ–साथ इधर से गुजरने वाले अन्य यात्रियों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।जिसके चलते पार्किंग व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने वहां पर मौजूद लखनऊ से आए अधिकारियों तथा स्थानीय रेल कर्मियों को निर्देश दिया कि इस गंभीर समस्या पर ध्यान दें और आसपास जमीन को चिन्हित करें जिससे पार्किंग की व्यवस्था बन सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो गया है तब से यहां पर श्रद्धालुओं की आवागमन में भी बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते यहां पर रेल यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाये। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही आरपीएफ उप निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन रचना यादव,मुख्य टिकट निरीक्षक अभिमन्यु सिंह सहित लखनऊ रेल मंडल से आए अधिकारी तथा कैंट रेलवे स्टेशन के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसके पश्चात डीआरएम लखनऊ रेल मंडल श्री वर्मा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन निरीक्षण करने के लिए निकल गए। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन ने बताया कि वहां पर उन्होंने स्टेशन परिसर के सभी प्लेटफार्म आरक्षण केंद्र प्रतीक्षालय सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन के साथ–साथ प्रभारी निरीक्षक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को निर्देश दिया कि आने वाले खासकर सावन मेला,15 अगस्त,रक्षाबंधन पर रेल यात्रियों के साथ–साथ श्रद्धालुओं की भीड़ में भी बढ़ोतरी हो सकती है इसके लिए रेल यात्रियों की सुविधा के साथ –साथ विशेष सतर्कता भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद डीआरएम रेलवे एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए।

संपादकीय

ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की घटती मौजूदगी

अध्ययन के दौरान 26 राज्योंध केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में करीब 7,800 लोगों के बीच सर्वेक्षण हुआ। उससे सामने आया कि ग्राम सभा की बैठकों लोगों की मौजूदगी घटती चली गई है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट का सार है कि ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था नाकाम होने के कगार पर है। रिपोर्ट– राज्यध केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभाओं में निम्न भागीदारी– शीर्षक से जारी हुई है। कहा गया है कि यह अध्ययन स्थानीय स्व–शासन पर देश के सबसे बड़े जमीनी आकलनों में से एक है। इसके तहत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में करीब 7,800 लोगों के बीच सर्वेक्षण किया गया। इससे सामने आया कि ग्राम सभा की बैठकों लोगों की मौजूदगी लगातार घटती चली गई है। आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि बैठकों में शामिल न होने की वजह रोजगार और कमाई से जुड़ी हैं। कामकाजी वर्ग के लिए काम–धंधा छोड़कर बैठक में आना कठिन होता है। फिर बैठकों में स्थानीय रसूखदार लोगों का ही दबदबा बना रहता है। रिपोर्ट में जिक्र है कि ग्राम सभाएं स्थानीय मुद्दों की पहचान करने में लगभग 13 प्रतिशत समय लगाती हैं, लेकिन राजस्व बढ़ाने के उपायों पर केवल चार फीसदी समय खर्च करती हैं। चूंकि केंद्रीय अनुदान से मिलने वाला पैसा काफी हद तक पहले से तय केंद्रीय प्राथमिकताओं (जैसे जल जीवन मिशन) से जुड़ा होता है, इसलिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक योजना पर अमल लगभग नामुमकिन ही बना रहता है। इस रूप में पंचायती राज संस्थाएं केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसी बन कर रह गई हैं। जबकि 73वें और 74वें संविधान में परिकल्पना उन्हें शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित करने की गई थी। वैसे, यह आरंभ में ही स्पष्ट हो गया था कि पंचायती संस्थाओं के लिए वित्त आयोग से तय अपना बजट और अपनी नौकरशाही नहीं होगी, तो उनका यही हाल होगा। फिर भी इस ओर कोई पहल नहीं हुई। इस सिलसिले में अक्सर उल्लेख होता है कि अमेरिका जैसी पूंजीवादी और चीन जैसी समाजवादी व्यवस्थाओं में एकमात्र समानता शासन का कारगर विकेंद्रीकरण है। दोनों जगहों पर इस नीति के सकारात्मक परिणाम जग–जाहिर हैं। मगर भारत में केंद्र हो या राज्य, अपने अधिकार क्षेत्र में कटौती के लिए तैयार नहीं हैं। नतीजा, ताजा रिपोर्ट में शामिल विलाप है।

संसद का मानसून सत्रः हंगामे नहीं, समाधान का संकल्प बने

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा बल उसकी संसद है। यही वह मंच है जहां देश की आकांक्षाएं, समस्याएं और भविष्य की दिशा तय होती है। संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श, जवाबदेही और जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है। ऐसे में 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा संसद का मानसून सत्र केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की परिपक्वता की नई परीक्षा भी है। देश की जनता की अपेक्षा है कि यह सत्र शोर–शराबे, आरोप–प्रत्यारोप और गतिरोध का नहीं, बल्कि सार्थक संवाद, गंभीर बहस और ठोस निर्णयों का सत्र बने। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में संसद के दृश्य लोकतांत्रिक गरिमा की अपेक्षा राजनीतिक टकराव के प्रतीक अधिक दिखाई दिए हैं। सदन में नीति और नीयत पर चर्चा कम तथा नारे, तख्तियां, वेल में प्रदर्शन और कार्यवाही बाधित करने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती रही है। संसद का प्रत्येक मिनट जनता के कर से चलता है, इसलिए उसका अनुत्पादक होना केवल संसदीय विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संसाधनों का भी दुरुपयोग है। संसद का उद्देश्य सरकार को घेरना अवश्य है, लेकिन केवल हंगामा खड़ा करना नहींय उसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल बहुमत के बल पर निर्णय लेना नहीं, बल्कि विपक्ष की बात सुनना और संवाद के लिए वातावरण बनाना भी है इस बार विपक्ष के पास अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर वह सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, सीमा सुरक्षा, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद, मन्दिरों में चोरी, कर व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया जैसे विषय निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन पर संसद में गंभीर चर्चा होना लोकतंत्र की आवश्यकता भी है और जनता का अधिकार भी। लेकिन यदि ये विषय केवल राजनीतिक नारेबाजी का माध्यम बनकर रह जाएं, तो उनका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। संसद में उठाया गया प्रत्येक मुद्दा समाधान की दिशा में बढ़े, यही लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रमाण होगा। विपक्ष लोकतंत्र का अनिवार्य स्तंभ है। उसका दायित्व केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना भी है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की आंख और कान दोनों होता है। यदि वह केवल विरोध की राजनीति तक सीमित हो जाए, तो उसकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर सरकार भी यदि विपक्ष के प्रत्येक प्रश्न को राजनीतिक षड्यंत्र मानकर संवाद से बचती है, तो लोकतंत्र का संतुलन कमजोर पड़ता है। इसलिए सत्ता और विपक्ष, दोनों को अपने–अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। मानसून सत्र में यदि शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होती है तो उसका केंद्र छात्रों का भविष्य होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ। यदि महंगाई पर बहस हो तो उसका उद्देश्य आम नागरिक को राहत देने वाली नीतियों पर विचार होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति अथवा सीमा संबंधी विषय उठते हैं तो उनमें दलगत राजनीति के बजाय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। संसद की बहस तब सार्थक कही जाएगी, जब उससे नीति निर्माण की दिशा निकले और जनता को यह विश्वास हो कि उसकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार हो रहा है। लोकतंत्र में बहस और असहमति कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। किंतु जब असहमति का स्थान अवरोध ले लेता है और बहस की जगह बहिष्कार आ जाता है, तब लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि संसद को चलाना ही लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी है। यह विचार आज पहले से अधिक प्रासंगिक है। संसद का ठप होना किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार है। इस समय देश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को बेहतर आय की अपेक्षा है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जरूरत है तथा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारत को अपनी विकास गति बनाए रखनी है। ऐसे समय संसद से जनता समाधान चाहती है, संघर्ष नहीं। यदि पूरा सत्र केवल राजनीतिक टकराव में बीत गया तो सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक का होगा, जिसकी आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। संसद की गरिमा केवल अध्यक्ष की कुर्सी या ऐतिहासिक भवन से नहीं बनती, बल्कि वहां बैठने वाले जनप्रतिनिधियों के आचरण से बनती है। सांसदों को यह स्मरण रखना चाहिए कि वे केवल अपने दल के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद में उनका प्रत्येक शब्द और प्रत्येक व्यवहार लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा बनता है। इसलिए व्यक्तिगत आरोपों और कटुता के स्थान पर तथ्यों, तर्कों और नीति आधारित विमर्श को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा रहा है कि वह विकास, सुशासन और नीति आधारित राजनीति में विश्वास रखती है। यदि ऐसा है तो उसे विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का तथ्यात्मक उत्तर देने में संकोच नहीं होना चाहिए। वहीं विपक्ष को भी यह समझना होगा कि केवल नारे लगाने अथवा कार्यवाही बाधित करने से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। उसे वैकल्पिक नीतियां, ठोस सुझाव और रचनात्मक आलोचना प्रस्तुत करनी होगी। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की सफलता संसद की सफलता से जुड़ी होती है। आज सूचना क्रांति के युग में जनता सब कुछ देख और समझ रही है। संसद में कौन बहस कर रहा है, कौन केवल राजनीतिक प्रदर्शन कर रहा है और कौन जनहित के प्रश्न उठा रहा है, इसका मूल्यांकन मतदाता स्वयं करता है। इसलिए अब केवल प्रतीकात्मक राजनीति से काम नहीं चलेगा।

जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करना होगा। दार्शनिक एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि संसद राष्ट्र के विवेक की आवाज होती है। यदि यही विवेक शोर में दब जाए तो लोकतंत्र का मार्ग भी धुंधला पड़ जाता है। इसलिए मानसून सत्र को ऐसे अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां सत्ता और विपक्ष मिलकर यह संदेश दें कि लोकतंत्र की असली शक्ति संवाद, सहमति और सार्थक बहस में निहित है। किसी भी आदर्श एवं मजबूत लोकतंत्र की अपेक्षा है विपक्ष का समक्ष एवं सकारात्मक सक्रिय होना। क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र की आंख है। लेकिन जब यह आंख केवल अंधविरोध में अंधी हो जाए, तो लोकतंत्र की दृष्टि धुंधली हो जाती है। जनता का दबाव ही विपक्ष को सद्बुद्धि दे सकता है। जब जनता यह स्पष्ट रूप से जताए कि उसे रचनात्मक, नीति आधारित विपक्ष चाहिए न कि नारेबाज नेता, तब विपक्ष को भी सुधरना पड़ेगा। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वह जनता की लड़ाई लड़ रहा है या केवल सत्तालोलुपता की राजनीति कर रहा है? मीडिया को चाहिए कि वह हंगामे को महिमामंडित करने के बजाय, नीति और तर्क आधारित बहस को आगे बढ़ाए। संसद में विवाद होना लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन वही विवाद अगर दिशा विहीन हो जाए, तो वह कमजोरी बन जाता है। आज जरूरत है कि संसद की गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाए, विपक्ष अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाए और सरकार भी अहंकार छोड़कर संवाद को अवसर दे। संसद यदि सचमुच ”लोक का मंदिर“ है, तो वहाँ केवल सत्ता की पूजा नहीं, लोकमंगल की बात होनी चाहिए, यही मानसून सत्र से बड़ी अपेक्षा है। इस सत्र में संसद का समय नीति निर्माण में ही लगे, वहां कार्यवाही स्थगित न हो। जनप्रतिनिधि जिन मुद्दों एवं उद्देश्यों को लेकर चुने जाते हैं, वे उन मुद्दों एवं उद्देश्यों पर खरे साबित हो। देश की जनता चाहती है ।

भोजशाला और ज्ञानवापी का नजराना देकर नजीर पेश करे मुस्लिम समाज

परमार वंश के महान राजा भोज द्वारा वर्ष 1034 में निर्मित यह संस्कृत पाठशाला और वाग्देवी मंदिर भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनुपम केंद्र था। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ीप) द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस स्थान के मूल स्वरूप को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। दो अंग्रेजी कहावते हैं जीम उपदक पे इसपदक” अर्थात् आँखें निरर्थक यदि दिमाग ही सत्य को देखने से इनकार कर दे। और दूजी कहावत है, ”थ्सवहहपदह ˙कमंक ˙वितेम“ अर्थात् मरे हुए घोड़े को चाबुक मार–मारकर उससे उठने की आशा रखना। ये दोनों ही कहावतें वर्तमान समय में 'भारतीय मुस्लिम समाज' पर सटीक बैठती हैं। धार की वाग्देवी (मां सरस्वती) की पावन धरोहर श्भोजशालाश और साथ–साथ काशीनाथ के ज्ञानवापी मंदिर का मामला आज पुनः मुस्लिम समाज से सौहाद्र की आशा लिए खड़ा है। मुस्लिम समाज और विशेषतः इस समाज के नेतृत्व का दावा करने वाले नेताओं को क्या यह बात समझ नहीं आती है कि – ”इस ऐतिहासिक परिसर पर हिंदू समाज का दावा केवल आस्था पर नहीं, बल्कि अकाट्य ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है? मुस्लिम समाज के नेता यदि अपनी सियासती स्वार्थों के कारण सही बात नहीं पर पा रहे हैं तो मुल्ला, मौलवी, मुस्लिम स्कालर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और भोजशाला व ज्ञानवापी का नजराना थाली में सजाकर हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। यदि मुस्लिम नेता और आलिम दोनों ही ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बार–बार गंगा जमुनी तहजीब की बात हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों को ही बंद कर देनी चाहिए। गंगा–जमुनी तहजीब केवल जुमला नहीं है यह मुस्लिम वर्ग को सिद्ध करने का यह सर्वाधिक सटीक अवसर है। परमार वंश के महान राजा भोज द्वारा वर्ष 1034 में निर्मित यह संस्कृत पाठशाला और वाग्देवी मंदिर भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनुपम केंद्र था। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस स्थान के मूल स्वरूप को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। सर्वेक्षण के दौरान परिसर और उसके मलबे से सनातन धर्म के विभिन्न देवी–देवताओं की खंडित एवं संरक्षित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें भगवान गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, माता पार्वती और वाग्देवी (सरस्वती) की अद्भुत कलाकृतियां सम्मिलित हैं। ये मूर्तियां स्पष्ट करती हैं कि यह मूल रूप से एक मंदिर परिसर था। भोजशाला की दीवारों और स्तंभों पर संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए कई शिलालेख मिले हैं। इनमें संस्कृत व्याकरण (पतंजलि के सूत्र), काव्य और राजा भोज की स्तुति अंकित है। मस्जिदों में अरबी या फारसी के शिलालेख होते हैं, परंतु यहाँ देवनागरी लिपि में खुदे वैदिक मंत्र और व्याकरण के नियम इस स्थान के अकाट्य श्सरस्वती कंठाभरणश (विद्या का मंदिर) होने की पुष्टि करते हैं। परिसर के स्तंभों, बीम और छतों पर नक्काशीदार कमल, स्वस्तिक, कलश, शंख, कीर्तिमुख और अप्सराओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। इस्लामी वास्तुकला में जीवंत आकृतियों का अंकन पूर्णतः वर्जित है, जबकि भोजशाला के कोने–कोने में ये कलाकृतियां बिखरी पड़ी हैं, जो इसके मंदिर होने का जीवंत प्रमाण हैं। वैज्ञानिक जांच में परिसर के भीतर प्राचीन हवन कुंड और गर्भगृह के स्पष्ट अवशेष मिले हैं। वर्तमान में जो ढांचा मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है, वह वास्तव में मंदिर के ही स्तंभों और सामग्री को उलट–पुलट कर तथा उन्हें क्षतिग्रस्त करके खड़ा किया गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, इस मंदिर की मूल अधिष्ठात्री देवी श्वाग्देवीश की प्रतिमा को ब्रिटिश काल में यहाँ से हटाकर लंदन के श्ब्रिटिश म्यूजियमश में रख दिया गया था, जिसके आधार पर भी हिंदू समाज का यह दावा वैश्विक स्तर पर सिद्ध होता है। इन तमाम वैज्ञानिक और पुरातात्विक तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि धार की भोजशाला पर हिंदू समाज का अधिकार पूरी तरह स्वाभाविक, ऐतिहासिक और न्यायसंगत है। ऐसे में, इस सत्य को नकारकर अदालतों में अपील दर अपील करना केवल समय की बर्बादी और समाज में कटुता बढ़ाने का माध्यम ही बनेगा। काशी की श्ज्ञानवापीश और धार की श्भोजशालाश दोनों ही स्थानों पर प्रत्यक्ष दिखने वाले पुरातात्विक साक्ष्य चिल्ला–चिल्लाकर सच्चाई बयां कर रहे हैं। सत्य को केवल कानूनी दांव–पेंचों से कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। न्यायालय भी अंततः साक्ष्यों और जनभावनाओं के संतुलन पर ही निर्णय देता है। ऐसे में फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना ष्अपनी ही कुल्हाड़ी पर पैर मारनेष जैसा है।

मुस्लिम समाज के नेताओं, मुल्ला–मौलवियों, बुद्धिजीवियों यह विचार करना ही चाहिए कि ऐसी हठधर्मिता भला किस काम की? वो क्यों अयोध्या जैसी जिद किए रहना चाहते हैं? हठधर्मिता का अंत हमेशा कड़वाहट के साथ होता है, जबकि संवाद का अंत सदैव सम्मान के साथ होता है। भारतीय मुसलमानों को यह ऐतिहासिक सत्य स्वीकार करना होगा कि उनके पुरखों के जींस और रक्त इस देश की मिट्टी से जुड़े है, किसी विदेशी आक्रांता बाबर या औरंगजेब से नहीं। वे इसी भूमि की संतान हैं। बहुसंख्यक हिंदू समाज ने सदियों तक अपने मानबिंदुओं के विध्वंस को मूक दर्शक बनकर झेला है, और अब स्वतंत्रता के बाद वह अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए आतुर है। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज को कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हिंदू समाज को श्बड़ा भाईश मानते हुए उन्हें आगे बढ़कर यह कहना चाहिएरू ष्ये स्थान आपकी आस्था के केंद्र हैं, हम स्वेच्छा से इन पर अपना दावा छोड़ते हैं। यह कदम मुस्लिम समाज की कमजोरी नहीं, बल्कि उनके बड़प्पन, सहिष्णुता और कथित श्गंगा–जमुनी तहजीबश का जीवंत उदाहरण बनेगा। जब बड़ा भाई अपने मानबिंदुओं को वापस पाने के लिए संघर्षरत हो, तो छोटे भाई का धर्म अड़चन बनना नहीं, बल्कि ससम्मान मार्ग प्रशस्त करना होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है ।

कृषि मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब–मिशन (एसएमएएम) के माध्यम से पूरे देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आधुनिक कृषि मशीनों तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। कृषि मशीनीकरण में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उन राज्यों एवं क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां कृषि यंत्रों का उपयोग अपेक्षाकृत कम है। योजना के शुरू होने से अब तक 9,404.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के माध्यम से देशभर के किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसके अलावा, 52.5 करोड़ रुपये की सहायता से 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र में 40,928 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इन प्रदर्शनों ने किसानों के बीच आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि यांत्रिकीकरण के माध्यम से खेती को सुदृढ़ बनाना भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मशीनीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के पूरे चक्र में विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें भूमि की तैयारी, बुआई, सिंचाई, फसल संरक्षण, कटाई एवं कटाई के बाद के प्रबंधन जैसे सभी प्रमुख कार्य शामिल हैं। कृषि मशीनीकरण से मानव और पशु श्रम पर निर्भरता कम होती है, जिससे कृषि कार्य समय पर, अधिक दक्षता व सटीकता के साथ पूरे किए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत घटती है, श्रम उत्पादकता बढ़ती है, कृषि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आय और खेती की समग्र उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब–मिशन (एसएमएएम) शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत केंद्र प्रायोजित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि मशीनों एवं उपकरणों का लाभ उन किसानों और क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इस योजना का विशेष ध्यान छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा ग्रामीण उद्यमियों पर है।

यह योजना कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना को बढ़ावा देती है। ये ऐसे केंद्र हैं, जहां कृषि मशीनें, औजार और उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं। यह योजना उच्च–प्रौद्योगिकी और महंगे कृषि उपकरणों के लिए हब स्थापित करने तथा कृषि मशीनरी के वितरण में भी सहायता प्रदान करती है। इसके तहत प्रदर्शन और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाती है। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर और कृषि शक्ति अपेक्षाकृत कम है। साथ ही, कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से सस्ती किराया सेवाएं उपलब्ध कराकर छोटे जोत आकार और अधिक लागत जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाता है। इसके अलावा, कृषि मशीनीकरण पर सब–मिशन के तहत कृषि मशीनरी के प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन को भी सहायता प्रदान की जाती है। इससे जुड़े हितधारकों के बीच इनका उपयोग बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। वर्ष 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की पर्याप्त स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि मशीनीकरण तथा मूल्य संवर्धन जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष 2017–18 में इस योजना का पुनर्गठन कर इसे आरकेवीवाई–रफ्तार (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण) के रूप में लागू किया गया, जिसमें फसल–पूर्व और फसलोपरांत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एसएमएएम के रणनीतिक स्तंभ कृषि यांत्रिकीकरण पर सब–मिशन (एसएमएएम) को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच बेहतर बनाकर, श्रम की आवश्यकता कम करके और खेती की उत्पादकता बढ़ाकर समावेशी तथा कुशल कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। प्रशिक्षण, परीक्षण, प्रदर्शन व फसल कटाई के बाद के कामों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना।

दतिया का एकता मॉडल कांग्रेस दूसरे राज्यों में लागू करे

शकील

छुट्टियां व मौसमी आयोजन पूरे देश में ऐसा ही माहौल है। लोग कांग्रेस को चाहते हैं। मगर उसके नेता ही उसकी जड़ें खोदते हैं। मोदी 12 साल में देश में और उनसे पहले के नेता 23 साल में जिसमें अटल और आडवानी का शासन भी रहा यह काम नहीं कर पाए हैं। राहुल अगर अपने नेताओं पर नियंत्रण कर लें तो उनकी जीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। राहुल गांधी को दतिया जाना चाहिए। देखें कि किस तरह कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। मध्य प्रदेश में 23 साल से कांग्रेस सत्ता के बाहर है। मगर फिर भी लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। यह कांग्रेस की गहरी जड़ें हैं। पूरे देश में ऐसा ही माहौल है। लोग कांग्रेस को चाहते हैं। मगर उसके नेता ही उसकी जड़ें खोदते हैं। मोदी 12 साल में देश में और उनसे पहले के नेता 23 साल में जिसमें अटल और आडवानी का शासन भी रहा यह काम नहीं कर पाए हैं। राहुल अगर अपने नेताओं पर नियंत्रण कर लें तो उनकी जीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। दतिया इसका मॉडल बन सकता है। और राहुल के विश्वासपात्र जीतू पटवारी इसके ब्रांड अम्बेसडर। समस्या क्या है कि प्रदेश के नेता पहली बात तो राहुल का नेतृत्व नहीं मानते हैं। दूसरी बात खुद को ही इतना समर्थ ओर लोकप्रिय मान लेते हैं कि कांग्रेस से आगे खुद को रखने लगते हैं।मध्य प्रदेश के उदाहरण से ही शुरू करते हैं। यहां 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता था। राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। और उन्होंने केवल मध्य प्रदेश ही नहीं जीता था। उसके साथ होने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव भी जीते थे। और इनसे पहले 2017 में गुजरात विधानसभा में भाजपा को हार के कगार पर ला खड़ा किया था। सौ से कम सीटों पर रोक दिया था। मुकाबला कितना कांटे का ले आए थे इससे समझ लीजिए कि 182 की विधानसभा में कांग्रेस को 80 और बीजेपी को 99 सीटें मिली। 45 साल के गुजरात के इतिहास में यह कांग्रेस का बेस्ट प्रदर्शन था। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी थे और उन्होंने गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार किया था।तो यही सिक्वेंस मध्य प्रदेश तक भी आया था। और 23 साल में यह उसकी एकमात्र जीत थी। लेकिन उस समय के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ यह समझे कि यह उनकी व्यक्तिगत जीत है। अहंकार में तो पहले ही रहते थे और इस जीत के बाद तो उनका दिमाग सीधा आसमान में पहुंच गया। कार्यकर्ताओं को छोड़िए बड़े–बड़े नेताओं को मिलने का समय नहीं। जीत में मुख्य भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को चौलेंज कर दिया कि जाओ सड़क पर उतर जाओ।गंवा दी अपनी सरकार। कांग्रेस में कमलनाथ भी अपने तरीके के एक ही केस हुए हैं। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिस समय उनको अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी तो हमने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से पूछा कि अरुण यादव उस समय के अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं अचानक कमलनाथ को अध्यक्ष बनाने की बात कैसे? जो जवाब हमें मिला वह भारी हैरान कर देने वाला था। बताया गया कि वे पैसा खर्च करेंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का निर्धारण इस बात पर कि वे पैसा खर्च करेंगे बहुत ही अनोखी बात थी। मगर उसके बाद उन्हें अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा भी बताना और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। कांग्रेस में पहले से किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है।खैर कमलनाथ की कथा अनंत है। उन्होंने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया। लेकिन उनके बाद आने वाले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस की मजबूत जड़ें उसके कार्यकर्ता हैं इसको पहचाना और उन्हें मजबूत करने और हिम्मत भरने का काम शुरू किया। दतिया इसकी मिसाल है। वे यहां पहले तो कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह का नामांकन भरवाने आए और उसके बाद फिर वापस आकर गांव–गांव के दौरे किए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में उनके पांच पंजे छा गए। कार्यकर्ताओं के साथ जनता में हौसला भरने के लिए उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपना फोन नंबर बताते हुए कहा कि कोई डराए–धमकाए, परेशान करे तो यह नंबर नोट कर लो। मुझे फौरन फोन करना। उन्होंने अपना नंबर बताते हुए कहा कि यह यह और यह और फिर पांच पंजे। मतलब पांच बार फाइव। दतिया में यह पांच पंजे चर्चा का विषय बन गए। कार्यकर्ताओं के साथ जनता के लोग भी एक दूसरे से पूछकर और उस सभा का वीडियो देखकर सही नंबर सेव कर रहे हैं। कार्यकर्ता जनता में हौसला ऐसे ही बनता है। चुनाव का माहौल खड़ा हो गया। कांग्रेस के हर राज्य में आपसी फूट और गुटबाजी है। हरियाणा, राजस्थान में इसकी वजह से चुनाव हारे। पंजाब, उत्तराखंड में अभी हैं। छह महीने के अंदर। लेकिन दोनों जगह गुटबाजी ने कार्यकर्ताओं को निराश कर रखा है। सरकार दोनों कांग्रेस की संभावनाओं वाले राज्य माने जा रहे हैं। लेकिन गुटबाजी कांग्रेस की जड़ें खोद रही है। राहुल को इसलिए दतिया का दौरा करके देखना चाहिए कि वहां किस तरह प्रदेश नेतृत्व ने स्थितियों को नियंत्रण में लिया है। और जीत का माहौल खड़ा किया है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद यहां कांग्रेस में दूसरे टिकट के उम्मीदवारों में नाराजगी थी। मगर कांग्रेस में ऐसा कम होता है कि टिकट के दावेदार सभी बाद में अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में काम करने लगें। जीतू पटवारी ने यह कारनामा किया। इसके बरअक्स भाजपा में भारी फूट दिखाई दे रही है। यहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर आरएसएस के एक प्रचारक आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। दतिया में यह दूसरा मौका है जब भाजपा ने इस तरह का प्रयोग किया हो। पहला तो असफल साबित हुआ था। 1977 विधानसभा में जनता पार्टी ने कई प्रमुख दावेदारों को नजरअंदाज करके एक अनाम आरएसएस के प्रचारक हरिहर निवास श्रीवास्तव को टिकट दिया था। और वे उस समय के कांग्रेस प्रत्याशी अभी जिन राजेन्द्र भारती की विधायकी रद्द हो जाने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है उनके पिता श्यामसुंदर श्याम से हारे थे। और बाद में हरिहर कांग्रेस में भी आ गए थे। अब यह दूसरा प्रयोग है जब आशुतोष को जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है उन्हें नरोत्तम जैसे भारी नेता के बदले चुनाव मैदान में उतारा गया है। उनकी जीत की संभावनाएं क्या हैं? खुद नरोत्तम ने कहा कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता लग गए तो? मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं के उनके पक्ष में लगने पर सवाल है। भाजपा के कार्यकर्ता नरोत्तम के पक्ष में जिस तरह खुल कर सामने आए थे उसने तो इतिहास बना दिया। भाजपा में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिला अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी और पंचायतों, नगरपालिका सबके अध्यक्षों ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया हो। भाजपा पूरी तरह बंटी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बड़ी खतरे की घंटी। इससे पहले एक विधानसभा उपचुनाव उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा हार चुकी है।

कम उम्र के लोगों में भी बढ़ रहे स्ट्रोक के मामले, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के डॉक्टरों ने दी चेतावनी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ।वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ, ने लोगों से ब्रेन हेल्थ के प्रति अधिक जागरूक रहने की अपील की है। अस्पताल के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बदलती लाइफस्टाइल, लंबे समय से अनियंत्रित बीमारियां और इलाज में देरी के कारण अब न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी तेजी से प्रभावित कर रही हैं। पिछले पांच वर्षों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोगों में जागरूकता बढ़ने और बेहतर डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होने से इन बीमारियों की पहचान पहले की तुलना में अधिक हो रही है। वहीं तनाव, पर्याप्त नींद न लेना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ती उम्र जैसे कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोविड के बाद के समय में नसों से जुड़ी बीमारियों और कम उम्र के लोगों में स्ट्रोक के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ, में न्यूरोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर – डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव, ने कहा, ष्स्ट्रोक और कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई हैं। हमारे पास 30 और 40 वर्ष की आयु के मरीज भी स्ट्रोक, नसों से जुड़ी बीमारियों और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के साथ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, धूम्रपान, तनाव, पर्याप्त नींद न लेना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं।

दीक्षांत की श्रृंखला में स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश,छात्राओं ने कराया चिकित्सकीय परीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एवं उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के पूर्व आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के

अंतर्गत छात्राओं के लिए विशेष स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 91 छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम विश्वविद्यालय पहुंची। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आवश्यक चिकित्सकीय सलाह भी दी गई। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि षनियमित स्वास्थ्य परीक्षण से बीमारियों की समय रहते पहचान हो जाती है, जिससे उनका प्रभावी उपचार संभव हो पाता है। स्वस्थ विद्यार्थी ही बेहतर शिक्षा प्राप्त कर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रो. रजनीश भास्कर, डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव, डॉ. मनोज कुमार पांडेय, डॉ. वनिता सिंह, डॉ. प्रियंका कुमारी सहित विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाला आरोपी इंदिरानगर पुलिस के हत्थे चढ़ा

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस आयुक्तालय लखनऊ की इंदिरानगर पुलिस ने जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को छह माह के लिए लखनऊ जनपद की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह प्रतिबंध के बावजूद अपने निवास क्षेत्र में पाया गया।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनिकेत कौशल उर्फ अमन (22 वर्ष) निवासी मायावती कॉलोनी, तकरोही, थाना इंदिरानगर के रूप में हुई है। आरोपी के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने के कारण संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार की अदालत द्वारा वाद संख्या 19(11)ध्2026 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा–10 के तहत कार्रवाई करते हुए 19 जून 2026 को उसे छह माह के लिए लखनऊ जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया गया था।पुलिस ने बताया कि जिलाबदर आदेश लागू होने के बावजूद आरोपी लखनऊ में ही रह रहा था। 18 जुलाई को थाना इंदिरानगर पुलिस ने उसे मायावती कॉलोनी स्थित पानी की टंकी के पास, तकरोही क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे थाने लाया गया और उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा–10 के तहत नया मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई।पुलिस के अनुसार जिलाबदर की कार्रवाई ऐसे अपराधियों के विरुद्ध की जाती है, जिनकी गतिविधियों से क्षेत्र की कानून–व्यवस्था और सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका रहती है। आदेश के बाद संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहना अनिवार्य होता है।

मड़ियांव पुलिस का बड़ा खुलासा- चोरी और मोबाइल स्नैचिंग गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार,

लखनऊ,(आरएनएस)। कमिश्नरेट लखनऊ की मड़ियांव पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पांच शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का लैपटॉप, आईपैड, महंगा मोबाइल फोन, आभूषण, घड़ियां तथा वारदात में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान एक अन्य मोबाइल चोरी के मामले का भी सफल खुलासा हुआ है, जबकि सैरपुर क्षेत्र के एक अन्य मुकदमे से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं।पुलिस के अनुसार 16 जुलाई 2026 को हरिओम नगर, गायत्री नगर निवासी मीना सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनके बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखे आभूषण, एक एसर लैपटॉप, एक एप्पल आईपैड, एटीएम पासबुक, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन की पासबुक, साउंड सिस्टम तथा एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए। इस संबंध में थाना मड़ियांव में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।इसी प्रकार 8 मई 2026 को ऑनलाइन ई–एफआईआर के माध्यम से एक अन्य मामले में केशवनगर निवासी तनवीर अहमद ने अपने सैमसंग गैलेक्सी एस–22 प्लस 5जी मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही थी।दोनों मामलों के खुलासे के लिए मड़ियांव पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों के माध्यम से आरोपियों की तलाश कर रही थी।

केराकत रजवाहा में तीन मगरमच्छ दिखने से दहशत, वन विभाग ने शुरू की निगरानी

दीपक श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में मड़ियाहूं कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव स्थित केराकत रजवाहा में पुलिया के पास मंगलवार सुबह तीन मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मगरमच्छों की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों ने बच्चों और पशुओं को रजवाहे के किनारे जाने से रोक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग और मड़ियाहूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन क्षेत्र अधिकारी विद्यासागर के नेतृत्व में डिप्टी रेंजर अतुल और अमित, वनरक्षक हिमांशु तथा कमला शंकर पांडेय की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छों की तलाश शुरू की। हालांकि, टीम के पहुंचने से पहले ही तीनों मगरमच्छ पानी में ओझल हो गए, जिससे उनका पता नहीं चल सका। वन विभाग की टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रजवाहे के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित निगरानी रखने तथा मगरमच्छों को सुरक्षित रेस्क्यू कर अन्य उपयुक्त स्थान पर छोड़े जाने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।इस मामले में जानकारी लेने पर वन क्षेत्र अधिकारी विद्यासागर ने बताया कि ग्रामीणों से तीन मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन फिलहाल मगरमच्छ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जंघई रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना निकली अफवाह, पुलिस–जीआरपी व सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सघन तलाशी अभियान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित जंघई रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह बम होने की सूचना मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने स्टेशन परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया सुबह करीब 6रू30 बजे मोबाइल नंबर 7318510060 से एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि जंघई रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस ट्रॉली बैग से बम जैसी आवाज आ रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मीरगंज, चौकी प्रभारी जंघई, जीआरपी प्रभारी समेत पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और परिसर के अन्य हिस्सों की बारीकी से जांच की, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध ट्रॉली बैग या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। सूचना देने वाले व्यक्ति ने बाद में अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। प्रारंभिक जांच में सूचना असत्य प्रतीत हो रही है। इसके बावजूद सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए आरपीएफ की सूचना पर प्रयागराज से बम निरोधक दस्ता भी मौके के पर पहुंच गया। फिलहाल जंघई रेलवे स्टेशन पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है और रेल संचालन सुचारु रूप से जारी है। पुलिस एवं रेलवे सुरक्षा बल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि सूचना झूठी साबित होती है, तो अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ऑपरेशन किरण के तहत बिजनौर पुलिस की पहल रंग लाई, काउंसलिंग से दो परिवारों में हुआ समझौता, टूटने से बचा रिश्ता

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस आयुक्तालय लखनऊ के दक्षिणी जोन में संचालित ऑपरेशन किरण के तहत थाना बिजनौर पुलिस ने पारिवारिक विवादों में हस्तक्षेप करते हुए दो परिवारों के बीच सफलतापूर्वक सुलह–समझौता कराया। पुलिस की काउंसलिंग और सकारात्मक संवाद के माध्यम से दोनों परिवारों को टूटने से बचाते हुए पति–पत्नी को पुनः साथ रहने के लिए सहमत कराया गया।पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन किरण के अंतर्गत थाना बिजनौर पुलिस को दो अलग–अलग पारिवारिक विवादों की जानकारी मिली थी। पहले मामले में थाना क्षेत्र के एक दंपति के बीच करीब 15 दिनों से विवाद चल रहा था। आरोप था कि पति शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसके कारण परिवार में लगातार तनाव बना हुआ था।दूसरे मामले में भी थाना क्षेत्र के एक दंपति के बीच लगभग एक माह से विवाद चल रहा था। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ गाली–गलौज करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध लगातार बिगड़ रहे थे।दोनों मामलों में थाना बिजनौर पुलिस ने पति–पत्नी और उनके परिजनों को थाने बुलाकर अलग–अलग एवं संयुक्त रूप से विस्तृत काउंसलिंग की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात धैर्यपूर्वक सुनी, उनकी समस्याओं को समझा और आपसी संवाद स्थापित कर मतभेद दूर करने का प्रयास किया। सकारात्मक परामर्श और समझाइश के बाद दोनों परिवारों ने पुराने विवादों को भुलाकर आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ पुनः एक साथ रहने पर सहमति व्यक्त की।पुलिस ने सुलह–समझौते के बाद दोनों परिवारों को शांतिपूर्ण वातावरण में नया जीवन शुरू करने की शुभकामनाओं के साथ उनके घर रवाना किया। इस दौरान दोनों पक्षों को भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संवाद बनाए रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता लेने की सलाह भी दी गई।पुलिस आयुक्तालय लखनऊ द्वारा संचालित ऑपरेशन किरण का उद्देश्य पारिवारिक विवादों, घरेलू कलह और सामाजिक तनाव के मामलों में संवेदनशील हस्तक्षेप कर परिवारों को टूटने से बचाना तथा संवाद और परामर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। बिजनौर पुलिस की इस पहल को इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

घर के चौनल में अचानक से उतरा करंट, छूने से विवाहिता को लगे झटके

लखनऊ, (संवाददाता)। अंबेडकरनगर के आलापुर थाना क्षेत्र के खतमीपुर गांव में सोमवार को घर के लोहे के चौनल में उतरे करंट की चपेट में आने से 23 वर्षीय विवाहिता रीमा चौहान की मौत हो गई, जबकि बचाव के दौरान उसके पिता रामशरण घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि रीमा चौहान पत्नी बृजमोहन इन दिनों अपने मायके खतमीपुर में रह रही थीं। उनकी छह माह की एक बेटी भी है। सोमवार को घर के चौनल में अचानक करंट उतर आया, जिसकी चपेट में गांव की सुनीता पत्नी प्रेमचंद आ गईं। सुनीता को बचाने के लिए रीमा दौड़ी, लेकिन वह स्वयं करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बेटी को बचाने के प्रयास में पिता रामशरण भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची आलापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक अनीता कमल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्यामनाथ शुक्ला, मंडल अध्यक्ष विनय पांडे, भाजपा नेता ज्योतिंद्रनाथ त्रिपाठी समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।

जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में सुरक्षित रखी वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जाए तथा सभी अभिलेख निर्धारित मानकों के अनुरूप अद्यतन रखे जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

डायट में विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा की विवरणिका का हुआ विमोचन

अयोध्या।मंगलवार को डायट में जिला समन्वयक डॉ अम्बिकेश त्रिपाठी एवं अभिषेक कुमार द्वारा प्रवक्ताओं, एस.आर.जी, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स एवं शिक्षकों आदि के माध्यम से विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा 2026–27 की विवरणिका का विमोचन हुआ।इस मौके पर इसके अलावा अभिमुखीकरण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।कार्यक्रम में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, शिक्षकों आदि द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने तथा राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान गतिविधियों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया।कार्यक्रम मे जिला समन्वयक डॉ त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान की प्रवृत्ति और भारतीय वैज्ञानिक विरासत के प्रति जागरूकता विकसित करने का राष्ट्रीय अभियान है।कहा कि वीवीएम विद्यार्थियों को विज्ञान को समझने, नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने तथा देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य ध्बीएसए लाल चन्द्र ने कहा कि वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है।कहा इससे आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता एवं नवाचार की भावना को नई दिशा बढती हैं।इस मौके पर डायट प्रवक्ता देवेन्द्र कुमार सिंह,ज्ञानेंद्र सिंह,डॉ ऋषि पाण्डेय,एस आर जी मनीष रस्तोगी, एस आर जी अमित मिश्रा और जिला समन्वयक विद्यार्थी विज्ञान मंथन अभिषेक कुमार मौजूद रहे।

पूर्वोत्तर रेलवे में न्यू बॉर्न बेबी देखभाल सप्ताह के तहत नवजातों को वितरित की गई बेबी किट

लखनऊ, (संवाददाता)। पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल में आयोजित श्न्यू बॉर्न बेबी देखभाल सप्ताहश् के अंतर्गत मंडल चिकित्सालय बादशाहनगर में जन्मे दो नवजात शिशुओं को बेबी केयर किट वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल, स्वच्छता और मातृ–शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रुति गुप्ता के मार्गदर्शन में दोनों नवजात शिशुओं को न्यू बॉर्न बेबी किट, वाटरप्रूफ शीट और डायपर प्रदान किए गए। इस दौरान नवजातों की माताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली गई।कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने माताओं को मंडल चिकित्सालय में उपलब्ध प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल संबंधी सुविधाओं की जानकारी दी तथा शिशुओं की स्वच्छता, पोषण और

नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर भी जागरूक किया।इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद्र, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. पाठक, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनामिका सिंह तथा पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की सदस्य उपस्थित रहीं।महिला कल्याण संगठन ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संगठन भविष्य में भी इसी प्रकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक नई विशेष जांच टीम गठित करने के संकेत दिए। कोर्ट ने कहा कि नई एसआईटी में पहले से जांच कर रहे अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच कराई गई है और उसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई है। एसआईटी की जांच के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए खुली अदालत में विस्तृत जानकारी साझा करना उचित नहीं होगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश (ब्श्र) ने कहा कि अदालत तीन–चार दिन बाद मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों की नई एसआईटी बनाई जाए, जिसमें पहले से जांच कर रहे अधिकारी भी शामिल हों। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को मामले का राजनीतिकरण न करने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यह एक साधारण आर्थिक अपराध का मामला है और जांच एजेंसियों को अपना काम स्वतंत्र रूप से करने दिया जाना चाहिए।

बीबीएयू में एक वर्षीय एलएलएम प्रवेश की अधिसूचना जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ के सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रवेश अंतिम मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें 70 प्रतिशत वेटेज प्रवेश परीक्षा और 30 प्रतिशत वेटेज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (एसओपी), कार्यानुभव (इंटर्नशिप) तथा शोध प्रकाशनों को दिया जाएगा।विश्वविद्यालय के अनुसार 30 अंकों के मूल्यांकन में कार्यानुभव के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित किए गए हैं।

भाकियू प्रदेश सचिव फरीद अहमद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने किया एसडीएम से मुलाकात

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)
अयोध्या।नवागत उप जिलाधिकारी सोहावल गजेंद्र सिंह को किसान नेता फरीद अहमद प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार वर्मा, कल्लू खान आदि ने औपचारिक मुलाकात कर बुके देकर फूल माला से सम्मानित किया।इस मौके पर किसान नेता फरीद अहमद ने बताया कि तहसील सुहावल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव में लेखपाल राजस्व निरीक्षक की लापरवाही से खतौनी में अंश निर्धारण ना होने की वजह से किसानो की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है क्षेत्र का किसान अपने खेतों में बेरन की रोपाई भी लगभग करवा चुका है खाद न मिलने के कारण किसान की फसल बर्बाद हो रही है शासन द्वारा आदेशित भी किया गया था कि राजस्व विभाग गांव–गांव में कैंप लगाकर किसान की खतौनी में अंश निर्धारण कर निशुल्क फार्मर रजिस्ट्री कराई जाए लेकिन राजस्व निरीक्षक लोग गांव गांव में कैंप न लगाने के कारण किसान सुविधा से वंचित रह गया है जिसकी शिकायत किसान दिवस में जिला अधिकारी महोदय से भी की जा चुकी है लेकिन तहसील क्षेत्र के लेखपाल राजस्व निरीक्षक की लापरवाही से किस की फसल बर्बाद हो रही है और सरकार की सुविधा का लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा है उप जिलाधिकारी सोहावल गजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बैठक कराकर किसानो का निस्तारण कराया जाएगा।

मानसून की बारिश व अतिवृष्टि से सजग रहने की जरूरत - सीएमओ

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)
अयोध्या। मानसून की बारिश व अतिवृष्टि से हम सभी को सजग रहने की जरूरत है।मानसून की बारिश के साथ ही संक्रमण, जलजनित रोगों और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।जिससे एक तरफ बाढ़ से जन जीवन तो प्रभावित होता ही साथ–साथ बीमारियों से भी आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।यह बाते सीएमओ डाक्टर देवेंद्र सिंह भिटौरिया ने कही।उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में अपने अपने परिवार की बाढ़ से बचाव एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जनपदवासियों से अपील की जाती है कि आप सावधानी और कुछ उपायों को अपना कर अपना एवं अपने परिवारजन को सुरक्षित रख सकते हैं।बाढ़ आने से पहले अफवाहों पर ध्यान न दें, शांत रहें, घबरायें नहीं।आपातकालीन संपर्क के लिये मोबाइल फोन सदैव चार्ज रखें।टी०वी० ६ समाचार पत्रों के माध्यम से मौसम की ताजा जानकारी रखें।मवेशियों ६ पालतू जानवरों के लिये उन्हें बांध कर न रखें।सुरक्षा एवं जीवन रक्षा के लिये आवश्यक वस्तुओं की इमरजेंसी किट प्राथमिक उपचार किट तैयार कर लें।बताया कि बाढ़ के पानी में वाहन न चलायें।बाढ़ के पानी में जाने से बचें और यदि जरूरी हो तो उचित जूते पहन कर ही जायें। सीवर लाइनों, गटरों, नालों, पुलियों आदि से दूर रहें साथ ही बिजली के खम्भोंद्यतारों से भी दूर रहें। ताजा पका हुआ अथवा सूखा खाना खायें व खाने को हमेशा ढंक के रखें। पानी उबाल कर पियें।कीटनाशकों ६ डिसइंफेक्टेंट के उपयोग से अपने घर एवं आस पास की जगहों को साफ व स्वच्छ रखें। गहरे पानी में मत उतरें, यदि आवश्यक हो तो पहले एक डंडे से पानी की गहराई का अनुमान लगा लें।इस समय आप पर्याप्त मात्रा में पानी पियें, ताजा और स्वच्छ भोजन खायें, अपने घरोंध्कूलर ६ कंटेनरध्नालियों ६ गढ्ढों ६ आस–पास पानी को इकठ्ठा न होने दें क्योंकि रूका हुआ पानी मच्छरों के पनपने के प्रमुख स्रोत होते हैं जो मच्छरजनित रोगों से लोगों में बीमारियां फैलाते हैं ऐसी स्थिति में समस्त रूके हुए पानी के निस्तारण व साफ–सफाई के प्रयासों से मच्छरजनित बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ायें, मच्छरों के काटने से बचाव करें।इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है और मच्छर सुबह व शाम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, मच्छरजनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचाव के लिये शरीर को ढकें व पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने, खिड़कियों पर जाली लगवायें और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, कोशिश करें कि नियमित व्यायाम की आदत अपनायें, तुरन्त चिकित्सा सहायता लें क्योंकि बीमारियों से होने वाली जटिलताओं को शीघ्र निदान द्वारा रोका जा सकता है जैसे लगातार बुखार, गंभीर दस्त, चकत्ते या सांस लेने में कठिनाई की स्थिति में तत्काल अपने नजदीकी सरकारी चिकित्सा ईकाई पर चिकित्सक से परामर्श करें व ईलाज कराये स्वयं से दवा लेने से बचें।बाढ़ एवं स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जनपद के भौगोलिक स्थिति के अनुसार बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव सरयू नदी से होता है। सरयू नदी में नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण कभी–कभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरयू नदी की बाढ़ का प्रभाव सामु० स्वा० केन्द्र सोहावल, रुदौली, पूराबाजार, मसौधा एवं मयाबाजार के कुछ क्षेत्रों तथा अयोध्या नगर एवं अयोध्या नगर के कुछ क्षेत्रों में होता है। कुछ भीतरी क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इन क्षेत्रों की बाढ़ चौकियाँ पूर्ववत् निर्धारित है, इन स्थानों पर विशेष ड्यूटी हेतु चिकित्सा अधिकारियों ६ कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। विभाग का पूर्ण प्रयास है कि पूर्वानुमान के आधार पर इन चौकियों पर ड्यूटी हेतु कर्मचारियो को सही समय पर सचेत कर दिया जाय, सभी सम्बन्धित अधिकारी ६ कर्मचारीगण का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दशा में बाढ़ प्रभावित परिवारों को संक्रामक रोगों से बचाव एवं उपचार व्यवस्था तत्काल करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु सा०स्वा० केन्द्र ६ प्रा०स्वा० केन्द्रों पर एक–एक सचल चिकित्सीय दल एम्बुलेंस के साथ तैनात रहेगा जो कि राहत शिविरों में जा कर बीमार लोगो का उपचार करेंगे। प्रत्येक विकास खण्ड के सा०स्वा० केन्द्र ६ प्रा०स्वा० केन्द्रों के अधीक्षक ६ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बाढ़ राहत कार्य के नोडल अधिकारी नामित है, जो अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही हेतु सीधे उत्तरदायी होगें।

महापौर ने किया स्थलीय निरीक्षण, पेयजल, सड़क और बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)
अयोध्या। आवास विकास कॉलोनी में वर्षों से बनी जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि आईटीआई के सामने स्थित पुराने नाले की खोदाई कर उसकी सफाई कराई जाएगी।इसके लिए रामपथ के फुटपाथ का आवश्यक हिस्सा हटाकर नाले को चालू किया जाएगा।जिससे कॉलोनी में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव से लोगों को राहत मिल सके।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पाण्डेय ने बताया कि निरीक्षण में अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, अधिशासी अभियंता राजपति यादव, सहायक अभियंता भारत सिंह वर्मा, अवर अभियंता अरुण कुमार, जलकल के सहायक अभियंता जयकुमार, जल निगम के सहायक अभियंता संजय, लोक निर्माण विभाग तथा परिवर्तन दल के अधिकारी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान नाले पर बिजली विभाग द्वारा स्थापित 11 हजार वोल्ट लाइन के कंट्रोल पैनल को हटाने का निर्णय भी लिया गया।इसके लिए बिजली विभाग से तत्काल पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। वहीं उदया चौराहा क्षेत्र के पास नाले की खोदाई कर उसे जालपा नाले से जोड़ने की योजना भी बनाई गई। उन्होंने बताया कि महापौर ने वशिष्ठ कुंड स्थित राघव विहार कॉलोनी का भी निरीक्षण किया। यहां अनुपयोगी बिजली के खंभे हटाने, पेयजल पाइपलाइन से सभी घरों को अभियान चलाकर कनेक्शन देने तथा गैर–विवादित हिस्से की सड़क निर्माण के लिए संशोधित प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय स्वीकृति लेने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने जलभराव और पेयजल संबंधी समस्याएं रखीं, जिनके समाधान के लिए महापौर ने अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए।

पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व निवर्तमान महानगर अध्यक्ष के साथ सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

(राजन तिवारी जिला संवाददाता)
अयोध्या। मंगलवार को पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार उपाध्याय को सौपा।पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी महानगर अयोध्या के नेताओं के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार उपाध्याय को सौपा गया, कचहरी गेट नंबर 1 पर भारी पुलिस बल ने रोकने कोशिश की लेकिन पूर्व मंत्री कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर ज्ञापन देने पर अड़े रहे अखिर में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन के माध्यम से मांग की गयी मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए, यदि कोई तकनीकी या वैधानिक कमी है तो उसको नियमानुसार संस्थान को दूर करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए, विश्विद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई परीक्षाएं व शैक्षिक गतिविधियां पर किसी भी तरह बाधित न हो!इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि ये सरकार शिक्षा विरोधी व छात्र विरोधी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर ध्वस्तीकरण से पहले वैकल्पिक विधियों पर विचार करना चाहिए,संशोधित मानचित्र की स्वीकृति, नियमितीकरण, कंपाउंडिंग, विकास शुल्क अथवा अन्य वैधानिक उपायों के माध्यम से भी मामलों का समाधान किया जा सकता है। किसी शैक्षणिक संस्थान पर ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए, ऐसी कार्यवाहियों से छात्र व उनके अभिभावक सभी परेशान है जो यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं!नि0 महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार छात्रों को उनकी मांगों को सुनने के बजाय लाठीचार्ज कर रही है चाहे जौहर विश्वविद्यालय का मामला हो और चाहे जंतर–मंतर पर छात्रों का धरना हो सिर्फ तानाशाही रवैये से आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है यही अवाज 2027 में सत्ता बदल देगी।इस सपा प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट ने बताया इस मौके पर नि0 महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, नि0महासचिव हामिद जाफर मीसम,प्रदेश सचिव राम अचल यादव, श्रीचंद यादव, प्रवक्ता राकेश यादव,शादाब खान, मंसूर इलाही एडवोकेट, फरीद कुरैशी, शावेज जाफरी एडवोकेट, मो सोहेल, अपर्णा जयसवाल , अमृत राजपाल, शादमान खान, माजिद खान बाबा, नूर बाबु, औरंगजेब खान, वसी हैदर गुड्डू, जगन्नाथ यादव, शीवांशु तिवारी, दान बहादुर सिंह, अंसार अहमद बबन, वीरेंद्र गौतम, चंदन यादव, मंजीत यादव, विशाल पाल पार्षद ,जगत नारायण यादव, सरजीत यादव, धर्मवीर, मंसूर प्रधान, अर्जुन यादव सोमू,वकार अहमद, राम आजोर यादव, राम भवन यादव नबी आलम, अजय यादव, ऋतुराज सिंह, लाल बहादुर शुक्ला एडवोकेट, कमलेश सोलंकी, शहबाज लकी, अनस खान, अजय मिश्रा, जितेंद्र यादव, विनय यादव बृजेश यादव, मो0 मारूफ, इत्यादि लोग मौजूद थे।

जनसुनवाई में छाया रहा जलभराव, सड़क, पेयजल व अतिक्रमण की प्रमुख मुद्दा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)
अयोध्या। नगर निगम के मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में नगर क्षेत्र के लोगों ने 25 प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी समस्याएं महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के समक्ष रखीं।इनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान की गई।जबकि शेष 12 मामलों में जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार भी मौजूद रहे।अयोध्या धाम जोनल कार्यालय में सुबह 10 बजे शुरू हुई जनसुनवाई में आवासीय पैमाइश, सड़क निर्माण, जलभराव से राहत, जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने, पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गईं। महापौर ने प्रत्येक प्रार्थना पत्र का गंभीरता से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।इस मौके पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने पेयजल पाइपलाइनों की नियमित जांच एवं आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश देते हुए कहा कि दूषित पेयजल की आपूर्ति रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे संक्रामक रोगों की आशंका को समय रहते समाप्त किया जा सके।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडे ने बताया कि जनसुनवाई में अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव,सुमित कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एम. शुक्ला, महाप्रबंधक जलकर सौरभ श्रीवास्तव, निर्माण खंड के सहायक अभियंता राजपति यादव, भरत सिंह वर्मा, जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी सहित नगर निगम के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जनगणना पुस्तिका तैयार किए जाने के संबंध में हुआ प्रशिक्षण

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'
'हरदोई' मंगलवार को जिला जनगणना अधिकारीध्अपर जिलाधिकारी (वित्तध्राजस्व) दीपाली भार्गव की अध्यक्षता में बालिका राजकीय इण्टर कालेज हरदोई में जिला जनगणना पुस्तिका (क्पेजतपबज ब्मदेने भ्ंदकइववा–क्ब्भ्) तैयार किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनगणना–2027 से संबंधित आंकड़ों, अभिलेखों एवं विभागीय सूचनाओं के संकलन, सत्यापन तथा व्यवस्थित रूप से तैयार किए जाने के संबंध में राजस्व विभाग के लेखपालों को जनगणना निदेशालय से नामित जिला प्रभारी विनय कुमार वर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण से दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्तध्राजस्व) ने लेखपालों को निर्देश दिए कि जनगणना निदेशालय से निर्गत परिपत्र के अनुसार जिला जनगणना पुस्तिका तैयार कर क्भ् पोर्टल पर फीड करते हुए आवश्यक आंकड़ों

एवं सूचनाओं को समयबद्ध एवं त्रुटिरहित रूप से क्भ् पोर्टल पर फीड किया जाएगा, उन्होंने कहा कि पुस्तिका में जिले की जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रामाणिक आंकड़ों का समावेश किया जाएगा। यह कार्यक्रम 16 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 सितंबर 2026 को सम्पन्न होगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियोंध्लेखपालों को निर्देशित किया कि अपने–अपने आवंटित क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं का भली–भांति परीक्षण कराते हुए निर्धारित प्रारूप में समय से पूर्व उपलब्ध कराएं, जिससे जिला जनगणना पुस्तिका को गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक ढंग से तैयार किया जा सके। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय से नामित जिला प्रभारी विनय कुमार वर्मा, चार्ज अधिकारीध्तहसीलदार सदर सचिन्द्र शुक्ला व जनगणना से अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

'पाली पुलिस ने सब्जी विक्रेता से हुई लूट का किया खुलासा'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'
'पाली–(हरदोई)' पुलिस ने सब्जी विक्रेता से मारपीट कर विक्की, मोबाइल फोन और नकदी लूटने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पाली–नकटौरा मार्ग पर भोरापुर जाने वाले रास्ते से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हर्षित उर्फ प्रिंसू पुत्र नत्थू सिंह उर्फ नथुनी, महेंद्र पाल उर्फ नन्हें पुत्र विशेश्वर उर्फ बद्री निवासी ग्राम भोरापुर थाना पाली,

नीरज शुक्ला पुत्र फौजदार निवासी ग्राम गोलोदपुर थाना भिगना जिला श्रावस्ती के रूप में हुई। प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि यह कार्यवाही सहजनपुर निवासी रामऔतार राठौर की तहरीर पर दर्ज मुकदमें के संबंध में की गई। आरोप है कि आरोपियों ने शनिवार देर शाम को वादी के चचेरे भाई बृजेश राठौर के साथ मारपीट कर उसकी विक्की, मोबाइल फोन तथा नकदी छीन ली थी जब वह भोरापुर से सब्जी बेचकर वापस लौट रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक विक्की, एक मोबाइल फोन, रुपये 2,800 नकद तथा दो डंडे बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की है।

रालोद की बैठक में बूथ स्तर पर संगठन के मजबूती जोर

गोरखपुर, (संवाददाता)। राष्ट्रीय लोक दल की मासिक बैठक रविवार को प्रेस क्लब में जिलाध्यक्ष महिपाल पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई। बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश मिश्र ने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय लोक दल की विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाएं और बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का संकल्प लें। बैठक का संचालन करते हुये क्षेत्रीय अध्यक्ष विवेक चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन विस्तार में जुटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव राजा ऐश्वर्या राज सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ताकत से ही राजनीतिक, सामाजिक लक्ष्य पूरे होंगे। मण्डल अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके सिद्धांतों और किसान हितैषी सोच को जन–जन तक पहुंचाना ही राष्ट्रीय लोक दल का उद्देश्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने का आह्वान किया। प्रदेश महासचिव अरुणेन्द्र पटेल ने कहा कि रालोद मजबूत हुई तो नौजवानों, किसानों का सपना साकार होगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करने का हम सबका लक्ष्य होना चाहिये। बैठक के दौरान संगठन की समीक्षा भी की गई तथा बूथ स्तर पर नई समितियों के गठन, सदस्यता अभियान को गति देने और गांव–गांव तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी कड़ी में रालोद के अध्यक्ष महिपाल पटेल का पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय महासचिव अरुण कुमार चौधरी, चौधरी, विवेक श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पशुओ को खुरपका-मुँहपका रोग से बचाने के लिये चलेगा 22 जुलाई से विशेष अभियान - सीवीओ

अयोध्या।सीवीओ अयोध्या डॉ. इंद्रदेव ने बताया कि जिले में पशुधन को खुरपका–मुंहपका (एफएमडी) जैसी संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए 22 जुलाई से 08 सितम्बर 45 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।अभियान के दौरान जिले के 136691 गोवंशीय और 302358 महिष वंशीय पशुओं को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए 29 टीमें गठित की गई हैं, जो रोस्टर के अनुसार गांव–गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी।बताया कि पशुपालकों से अभियान में सहयोग करने और निर्धारित समय के अंदर अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की अपील की गई है।उन्होंने बताया कि पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 136691 गोवंशीय और 302358 महिष वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। चार माह से कम उम्र के बछड़ों तथा आठ माह से अधिक गर्भित पशुओं को इस अभियान में शामिल नहीं किया जाएगा। अभियान के सुचारु संचालन के लिए प्रत्येक विकासखंड में प्रभारी अधिकारी नामित किए गए हैं।खुरपका–मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है।इसकी चपेट में आने पर पशुओं को तेज बुखार, मुंह से अत्यधिक लार गिरना, मुंह और पैरों में छाले पड़ना, चारा छोड़ देना तथा दूध उत्पादन में भारी कमी जैसी समस्याएं होती हैं।गंभीर स्थिति में गर्भित पशुओं का गर्भपात हो सकता है और समय पर उपचार न मिलने पर पशु की मौत भी हो सकती है।विदेशी नस्ल की गायों में इस बीमारी का खतरा अधिक रहता है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।